

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला परिवीक्षा अधिकारी, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला परिवीक्षा अधिकारी, चम्पावत के माह 12/2015 से 04/2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 02.06.2017 से 06.06.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

#### भाग-I

1). परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री र व शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री वी.पी. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2015 से 19.12.2015 तक श्री डी.एन. मश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2012 से 11/2015 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में 12/2015 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: इकाई द्वारा जनपद के अंतर्गत राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा महिला कल्याण के लिए संचालित वधवा पेंशन योजनाओं, सामान्य जाति वर्ग गौरा देवी कन्याधन योजना आदि योजनाओं का संचालन एवं अनुश्रवण किया जाता है।

(अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

( लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आ धक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आ धक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	Nil	Nil	0.00	0.00	0.00	394.75	389.09	5.66
2015-16	Nil	Nil	0.08	0.06	0.02	426.79	426.79	0.00
2016-17	Nil	Nil	0.10	0.10	0.00	594.05	594.05	0.00

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

(रु. लाख में)

योजना का नाम	2015-16			2016-17		
	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	-	28.74	28.74	-	27.65	27.65

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'स' श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

सचिव, समाज कल्याण → निदेशक, समाज कल्याण → जिला परिवीक्षा अधिकारी

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में जिला परिवीक्षा अधिकारी, चम्पावत को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वतरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण जिला परिवीक्षा अधिकारी, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित किया गया प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1 - गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत धनराश उपलब्ध होने के बावजूद भी 517 लाभार्थियों को लाभान्वित न किया जाना।

शासनादेश संख्या: 749/XVII-4/2016-01(135) 2013- टी. सी-1 (05/16) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 से गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृत करने तक की समस्त प्रक्रियाओं को आन लाईन किया जाएगा। गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत लाभ पाने हेतु निम्न पात्रता होनी चाहिए:-

- (I) शासनादेश के अनुसार योजना हेतु पात्र गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रु 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं 21206/-शहरी क्षेत्र में, से अधिक न हो।
- (II) योजना का लाभ केवल इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को ही दिया जायेगा एवं व्यक्तिगत छात्रा के सम्बन्ध में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली केवल अविवाहित छात्रा पात्र होगी तथा उसकी उम्र उस शैक्षिक वर्ष के माह की 01 जुलाई को 25 वर्ष से अधिक न हो।
- (III) योजना के अन्तर्गत चयनित प्रति छात्रा रु 50000 की धनराशि कन्याधन के रूप में स्वीकृत की जायेगी। धनराशि का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा ऐसे शासकीय बैंक जो सी बी एस माध्यम से जुड़े हैं में छात्रा के नाम से तीन से पाँच वर्ष के अवधि की सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जायेगी तथा जिस पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुसार मासिक ब्याज दिया जायेगा। सावधि जमा की समय सीमा समाप्त होने पर बालिका को मूलधन प्रदान किया जाएगा।

उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 03 के (VII) में स्पष्ट प्रावधान था क योजना के अंतर्गत समस्त पात्र लाभार्थी को वर्ष 2016-17 से धनराश आनलाईन प्रेषित किया जायेगा। कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत के वर्ष 2016-17 के योजना से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया क सामान्य वर्ग के कुल 1047 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसके लए शासन द्वारा फरवरी 2017 में रु. 258.50 लाख अवमुक्त कये गये। जिसे इकाई द्वारा कोषागार से आहरित कर संचालित बैंक खाते में रखा गया था। उक्त आवंटित धनराश से 517 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सकता था, परन्तु सम्प्रेक्षा तिथि (05/17) तक लाभार्थियों को वितरित नहीं किया गया था। जब क अनुदान का भुगतान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए था। यहाँ तक भी उल्लेखनीय है क शासनादेश के प्रावधानुसार समस्त भुगतान प्रक्रिया आनलाईन किया जाना था परन्तु इकाई द्वारा उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए धनराश का कोषागार से आहरण कर बैंक खाते में रखा गया तथा लाभार्थियों को आफलाईन प्रक्रिया के अनुसार भुगतान कये जाने की प्रक्रिया गतिमान थी। इस प्रकार से वर्ष 2016-17 के कुल पात्र 1017 बालिकाओं को वर्तमान तक लाभान्वित नहीं किया

गया। जाँच में यह भी पाया गया क क वभाग द्वारा कसी भी छात्रा को साव ध जमा पर मा सक ब्याज का भुगतान नही प्रदान कया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया क लाभार्थियों को भुगतान हेतु बैंक से साव ध जमा बनाकर वतरण की कार्यवाही गतिमान है। आनलाईन भुगतान न कये जाने के संबंध में अवगत कराया क बजट आवंटन मार्च माह के अंत में होने के कारण लाभार्थियों को भुगतान आनलाईन नहीं कया जा सका तथा भवष्य में आनलाईन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराश रू. 258.50 लाख का आवंटन दिनांक 14.02.2017 को कया गया था। अतः यह कहना क आवंटन मार्च माह के अन्त में कया गया है, सत्य नहीं है। अतः गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत धनराश उपलब्ध होने के बावजूद भी 517 लाभार्थियों को लाभान्वित न कये जाने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- वधवा पेंशन के शत प्रतिशत सत्यापन के अभाव में रु. 4.27 लाख की धनराश अवरोद्ध रखना।

शासनादेश (06/2016) के अनुसार निराश्रित वधवा भरण-पोषण अनुदान योजना के ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जो बी.पी.एल. श्रेणी के अंतर्गत आता हो अथवा जिसकी मासिक आय रु. 4000/- निर्धारित हो। पेंशन की दरें रु. 1000/- प्रतिमाह की दर से देय होंगी। योजना के अनुसार निराश्रित वधवाओं को अपने भरण पोषण हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र हेतु ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र हेतु सहायक समाज कल्याण अधिकारी/सहसिलदार को देना होगा जिसमें पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर इत्यादि की जांच के उपरान्त वधवा पेंशन स्वीकृत की जाती है। लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में लखत आवेदन पत्रों पर वचार करने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। शहरी क्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्रों पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी/सहसिलदार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। वधवा पेंशन की धनराश लाभार्थियों को माह के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर वितरित की जायेगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ कश्त का भुगतान क्रमशः जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च के अन्त तक किया जाना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड सचवालय के मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय प्रपत्रांक संख्या 443 दिनांक 16 मार्च 2016 के अनुपालन में स्पष्ट प्रावधान था कि जनपद में संबंधित जिला अधिकारी के पर्यवेक्षण में एवं ग्रामीण में मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में लाभार्थी के सत्यापन में शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराया जाये।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, चम्पावत के वर्ष 2016-17 के निराश्रित वधवा भरण-पोषण अनुदान योजना के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाली वधवा पेंशनरों का वधवत सत्यापन शत-प्रतिशत नहीं किया जा रहा था। जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय में 142 लाभार्थियों के रु. 4.27 लाख वधवत बैंकों एवं मृत्यु हुए पेंशनरों की ब्लाकों से धनराश प्राप्त हुई है एवं कार्यालय स्तर पर अवरोद्ध पड़ी है। सत्यापन के अभाव में यह पता ही नहीं चल पाता है कि पेंशन के रूप में निर्गत की जा रही धनराश वास्तविक रूप से पात्र जीवित वधवा या पात्र लाभार्थी को ही प्रदान की जा रही है या नहीं। कार्यालय के पास इस तरह का कोई तंत्र/अभिलेख वद्यमान नहीं था जो यह सुनिश्चित कर सके कि त्रैमासिक भुगतान किए जाने से पूर्व मृत्यु की सूचना तिथि सहित कार्यालय को प्राप्त हो रही हो। कार्यालय के पास लेखापरीक्षा अवधि तक इससे वदित है कि योजना के अंतर्गत प्रदत्त की

गई धनरा श ऐसी वधवाओं को भी दी गयी थी जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी थी या आपात्र थे। यदि वभाग द्वारा शत-प्रतिशत सत्यापन कया जाता तो उक्त वसंगति से बचा जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत करने पर इकाई ने कहा क जनपद में शत प्रतिशत सत्यापन पूर्ण कया गया है एवं अवरूद्ध धनरा श के संबंध में इंगत करने पर प्रकरण की पुनः जांच कर अप्रयुक्त धनरा श को जमा कया जायेगा। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है। क्यो क शत प्रतिशत सत्यापन के संबंध में कोई भी साक्ष्य सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये है। जिसके फलस्वरूप 142 लाभार्थियों की रू. 4.27 लाख की धनरा श इकाई स्तर पर अवरूद्ध पडी है।

अतः वधवा पेंशन के शत प्रतिशत सत्यापन के अभाव में रू. 4.27 लाख की धनरा श अवरूद्ध रखना का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

### भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
146	2015-16	शून्य	शून्य	शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-Vआभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला परिवीक्षा अधिकारी, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत अनियमतताए: शून्य

3). लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री पी.सी. जोशी	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनियमतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रेषित कर दी जाय।



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी  
(सामाजिक क्षेत्र)